ISSN: 2349-1876 (Print) | ISSN: 2454-1826 (Online)

'केंद्र सरकार की नीतियाँ और विकसित भारत का लक्ष्य' के संदर्भ में 'विकासमूलक पत्रकारिता'

अभिलाष,

शोधार्थी, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

शोध–सार

भारत एक विकासशील देश से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तीव्र गति से अग्रसर है। इस प्रक्रिया में जहाँ केंद्र सरकार की विकासोन्मुख नीतियाँ–जैसे आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत, मेक इन इंडिया आदि–देश के आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी उत्थान को दिशा दे रही हैं, वहीं इन योजनाओं की जानकारी, प्रभाव मूल्यांकन और जनभागीदारी सुनिश्चित करने में विकासमूलक पत्रकारिता एक महत्त्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभर रही है। विकासमूलक पत्रकारिता केवल समाचार प्रसारण तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह समाज को जागरूक करती है, नीति–निर्माताओं तक जनभावनाएँ पहुँचाती है और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का उत्प्रेरक बनती है। यह पत्रकारिता उन मुद्दों पर केंद्रित रहती है जो आम नागरिकों के जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण और सांस्कृतिक समरसता से सीधे जुड़े हैं। सरकार की विकास योजनाओं और पत्रकारिता के इस संवादात्मक संबंध के माध्यम से ''विकसित भारत 2047'' के लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। हालाँकि मीडिया पर राजनीतिक या व्यावसायिक दबाव, ग्रामीण क्षेत्रों से रिपोर्टिंग की कमी और संसाधन–संबंधी चुनौतियाँ अभी भी बाधा बनी हुई हैं। अतः स्वतंत्र, निष्पक्ष और समाजोन्मुख विकास पत्रकारिता को प्रोत्साहित करना आवश्यक है ताकि शासन और जनता के बीच पारदर्शिता, जवाबदेही और सहभागिता का वातावरण निर्मित हो सके। इस प्रकार, विकासमूलक पत्रकारिता न केवल सूचना का माध्यम है, बल्कि यह लोकतांत्रिक और समावेशी विकास की दिशा में एक सशक्त सेतु के रूप में कार्य करती है।

बीज शब्द : *विकासमूलक पत्रकारिता, विकास संचार, केंद्र सरकार की नीतियाँ, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, विकसित भारत 2047, सामाजिक जागरूकता, जनभागीदारी, नीति मूल्यांकन, समावेशी विकास, जनहित पत्रकारिता।*

भारत एक विकासशील देश से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। इस यात्रा में जहाँ सरकार की नीतियाँ और योजनाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, वहीं इन योजनाओं की जानकारी, निगरानी और आलोचनात्मक मूल्यांकन के लिए विकासमूलक पत्रकारिता एक आवश्यक कड़ी बन चुकी है। वर्तमान दौर में पत्रकारिता का कार्य केवल समाचार देना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक कर नीतियों के प्रभाव और निष्पादन पर रोशनी डालना भी है। इस संदर्भ में, भारत की केंद्र सरकार की विकासोन्मुख नीतियाँ और विकासमूलक पत्रकारिता का पारस्परिक संबंध अत्यंत महत्त्वपूर्ण बन जाता है।

विकास संबंधी मूलभूत संकल्पनाएँ

- विकास का अर्थ है, अधिकांश व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन में बगैर शोषण या हिंसा के स्थायी रूप से

सकारात्मक परिवर्तन लाना।

- संचार के अधिकांश भागों में विकास द्वारा व्यापक निरक्षरता, जनसंख्या, कुपोषण, खराब स्वास्थ्य, भूख तथा प्रदूषण आदि की समस्याओं का सामना करने के लिए गहन प्रयास करने की आवश्यकता है।

विकास पत्रकारिता अपेक्षाकृत नयी संकल्पना है। यह उपनिवेशी युग के समाप्त होने पर अस्तित्व में आयी। स्वाधीनता से पहले संघर्ष, लड़ाई—झगड़े, हत्याएँ, आपदाएँ, युद्ध और अन्य ऐसे मामलों के ही समाचार लोगों को दिए जाते थे,जो उपनिवेशी शासक चाहते थे। भारत जैसे—नयी स्वाधीनता प्राप्त किए हुए देशों में विकास क्रियाकलापों का बहुत विस्तार हो रहा था। पत्रकार और सूचना देने वालों को इन क्रियाकलापों को ध्यान में रखना होता है। आज कल विकास पत्रकारिता ऐसे व्यक्तियों की सफलता के समाचार पर ध्यान केंद्रित करती है, जिन्होंने नयी प्रौद्योगिकियाँ अपनाई हैं, नयी विधियों का परीक्षण किया है और समाज की सहायता की है। यह नयी परियोजनाओं तथा नयी प्रक्रियाओं में कार्य कर रहे व्यक्तियों का विवरण प्रदान करती है।

विकासमूलक पत्रकारिता का अर्थ है— संचार की क्षमता को सामाजिक विकास के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक की भाँति उपयोग में लाना। यह सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से प्रक्रियाओं, योजनाओं तथा संचार के सिद्धांतों को क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग करने की विधि है। 'डेवलेपमेंट कम्यूनिकेशन' (अर्थात विकास संचार) शब्द को सबसे पहले 1972 में नोरा क्यूब्राल (छवतं फनमइतंस) ने प्रयोग किया। यह कला तथा मानवीय संचार का वह विज्ञान है, जिसका उपयोग किसी अभावग्रस्त समाज के विकास की गति को तीव्र करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है जिससे समानता तथा व्यक्ति की क्षमता को सुनिश्चित किया जा सके।

विकासमूलक पत्रकारिता का स्वरूप और उद्देश्य

विकासमूलक पत्रकारिता वह पत्रकारिता होती है जो समाज, देश और नागरिकों के समग्र विकास से जुड़ी गतिविधियों, योजनाओं और समस्याओं को केंद्र में रखकर रिपोर्टिंग करती है। इसका उद्देश्य केवल समाचार देना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना होता है। इसे "सकारात्मक पत्रकारिता" या "जनहित पत्रकारिता" भी कहा जाता है। विकासमूलक पत्रकारिता केवल घटनाओं की रिपोर्टिंग नहीं करती, बल्कि समाज को सकारात्मक दिशा में ले जाने वाला एक सक्रिय माध्यम बनती है। यह पत्रकारिता का वह रूप है जो समाज के व्यापक हित को प्राथमिकता देता है।

विकासमूलक पत्रकारिता की भूमिका

विकासमूलक पत्रकारिता, जिसे अंग्रेजी में क्मअमसवचउमदजंस श्रवनतदंसपेउ कहा जाता है, समाज के सतत विकास और सकारात्मक बदलाव की दिशा में कार्य करने वाली पत्रकारिता है। इसका उद्देश्य केवल समस्याओं को उजागर करना नहीं है, बल्कि उनके समाधान की ओर भी समाज का मार्गदर्शन करना है।

इस संदर्भ में विकासमूलक पत्रकारिता की भूमिका निम्नलिखित हैः—

- **नीतियों की जानकारी देना—** एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाना पत्रकारिता का पहला कार्य है। जब लोगों को योजनाओं के लाभ और उद्देश्यों की जानकारी मिलती है, तो वे स्वेच्छा से इसमें भाग लेते हैं।
- **सांस्कृतिक संवाद को बल देना—** पत्रकारिता विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक विशेषताओं,

परंपराओं, बोलियों और लोक–कला को मुख्यधारा में लाकर एकता की भावना को बल देती है। इससे आपसी समझ और सौहार्द बढ़ता है।

- **सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करना–** विकासमूलक पत्रकारिता उन क्षेत्रों के उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है, जहाँ यह योजना प्रभावी रही है, जिससे अन्य क्षेत्रों को भी प्रेरणा मिलती है।
- **नीति–निर्माताओं तक जनभावनाएँ पहुँचाना–** पत्रकारिता समाज की प्रतिक्रिया, सुझाव और आलोचनाओं को सरकार तक पहुँचाकर नीति में सुधार का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।
- **समाज में जागरूकता और भागीदारी–** जब पत्रकारिता विकास के मुद्दों–जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सांस्कृतिक समावेशिता–पर ध्यान केंद्रित करती है, तो नागरिकों में जागरूकता और भागीदारी बढ़ती है।

विकासमूलक पत्रकारिता के प्रमुख तत्त्व

1. **समाज के विकास पर फोकस :** इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, कृषि, रोजगार, ग्रामीण विकास, स्वच्छता आदि जैसे विषयों को प्रमुखता दी जाती है।
2. **समस्याओं की गहराई से पड़ताल :** यह केवल समस्या बताने तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसके कारण, प्रभाव और समाधान की दिशा में भी जानकारी देती है।
3. **सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करना :** विकासमूलक पत्रकारिता उन लोगों, संस्थाओं या पहलों को सामने लाती है जो समाज में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं।
4. **नीतियों की समीक्षा :** यह सरकारी योजनाओं और नीतियों का विश्लेषण करती है कि वे जमीनी स्तर पर कैसे लागू हो रही हैं और उनके परिणाम क्या हैं।
5. **जन–संवेदनशीलता और भागीदारी :** यह पत्रकारिता जनता की भागीदारी को बढ़ावा देती है और सामाजिक चेतना जगाती है।

विकासमूलक पत्रकारिता का महत्त्व

- समाज में जागरूकता फैलती है।
- नीति निर्माताओं तक जमीनी हकीकत पहुँचती है।
- हाशिए पर खड़े वर्गों की आवाज को मंच मिलता है।
- सामाजिक बदलाव और सुधार के प्रयासों को बल मिलता है।

उदाहरण

- किसी गाँव में महिला स्व–सहायता समूह द्वारा किए गए रोजगार सृजन पर रिपोर्ट करना।
- एक स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के स्थानीय प्रयासों को उजागर करना।
- जल संरक्षण के लिए किसी ग्रामीण क्षेत्र में चल रही पहल को प्रमुखता देना।

विकासमूलक पत्रकारिता की मुख्य विशेषताएँ हैं

- यह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक

विकास तथा व्यक्तियों व सामान्य जन–समुदाय की सुख–शांति की ओर उन्मुख है।

- इसका उद्देश्य समुदाय को सूचना देना तथा शिक्षित करना है।
- अधिक प्रभाव के लिए यह उपयुक्त जनसंचार साधनों तथा अंतर्वैयक्तिक संचार चौनलों को जोड़ता है।
- यह श्रोताओं की विशिष्टताओं तथा उनके परिवेश पर आधारित है।

विकास संचार ऐसे दो पक्षों के बीच दो–तरफा संप्रेषण है, जिसमें एक के पास सूचनाएँ हैं तथा दूसरा उससे अनभिज्ञ है। यह ऐसा मानता है कि जो व्यक्ति समय का सामना करते हैं, उनमें उसका हल ढूँढने की स्वाभाविक क्षमता होती है, उन्हें संसाधन जुटाने में सहायता की आवश्यकता महसूस हो सकती है। यह अभिप्रेरण को घटक के रूप में देखता है। यह व्यक्तियों तथा विकास एजेंसियों के बीच संवाद बनाने का प्रयत्न करता है। इसलिए यह एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है,जिसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि इसमें सम्मिलित सभी सहभागियों के बीच एक आम सहमति या समझ उत्पन्न हो, जिससे वे संगठित कार्रवाई कर सकें।

विकासमूलक संचार के साधनों के रूप में पत्रकारिता, रेडियों/टेलीविजन/मुद्रण माध्यमों/वीडियो पर अभियान आदि है, जिसके माध्यम से हम विकास संचार की पहल के कुछ विशिष्ट जानकारी पाते रहे हैं,जैसे–धूम्रपान की रोकथाम, तपेदिक, एच. आई. वी/एड्स तथा साक्षरता को बढ़ावा देना, टीकाकरण, सुरक्षित प्रसव तथा 'जागो ग्राहक जागो' जैसे अभियान से उपभोक्ता की जागरूकता।

विकासमूलक पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित, पिछड़े और ग्रामीण वर्गों की आवाज को सामने लाना, विकास योजनाओं की जमीनी सच्चाई उजागर करना और सरकार तथा समाज के बीच एक सक्रिय सेतु का कार्य करना है। यह पत्रकारिता नीति–निर्माताओं को फीडबैक प्रदान करती है और समाज को यह जानकारी देती है कि उनके हित में बनी योजनाएँ कितनी कारगर हैं।

केंद्र सरकार की नीतियाँ और विकसित भारत का लक्ष्य

भारत एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जो 21वीं सदी में एक वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न नीतियाँ और योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जो देश को 'विकसित भारत' की दिशा में ले जाने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। ये नीतियाँ न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं, बल्कि सामाजिक समावेशन, पर्यावरण संरक्षण और तकनीकी प्रगति को भी समान रूप से महत्त्व देती हैं।

1. आर्थिक सुधार और आत्मनिर्भर भारत अभियान

भारत सरकार का 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इसके अंतर्गत उत्पादन में 'मेक इन इंडिया', स्टार्टअप इंडिया, और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ शुरू की गई हैं। इनसे घरेलू उद्योगों को मजबूती मिल रही है और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।

2. डिजिटल इंडिया और तकनीकी सशक्तिकरण

'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के अंतर्गत देश को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी, ई–गवर्नेंस, ऑनलाइन सेवाएँ, और डिजिटल शिक्षा की सुविधाएँ पहुँचाकर सरकार ने डिजिटल समावेशन को संभव किया है। यह अभियान न

केवल सुविधा बढ़ाता है, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित करता है।

3. स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार

'आयुष्मान भारत' जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार ने व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएँ सुलभ कराई हैं। इसी तरह 'नई शिक्षा नीति 2020' के अंतर्गत छात्रों में कौशल विकास और नवाचार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह नीति भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।

4. पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास

'हरित भारत मिशन', 'स्वच्छ भारत अभियान', और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली योजनाओं से यह स्पष्ट होता है कि सरकार आर्थिक विकास के साथ–साथ पर्यावरणीय संतुलन को भी प्राथमिकता दे रही है। 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भी इसी दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

5. इन्फ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी

'प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना', 'भारत माला', और 'उड़ान योजना' जैसी पहलें देश की भौतिक संरचना को आधुनिक बना रही हैं। सड़कों, हवाई अड्डों, रेलवे और लॉजिस्टिक नेटवर्क का विस्तार देश के कोने–कोने को जोड़कर आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान कर रहा है।

विकसित भारत का लक्ष्य केवल आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक समावेशी, टिकाऊ और समानतापूर्ण समाज के निर्माण का संकल्प है। केंद्र सरकार की नीतियाँ इस लक्ष्य को पाने की दिशा में बहुआयामी प्रयास कर रही हैं। यदि इन नीतियों का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से होता रहा, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में वैश्विक मंच पर अग्रणी भूमिका निभाएगा।

केंद्र सरकार की प्रमुख विकास योजनाएँ (विकसित भारत के संदर्भ में)

भारत सरकार ने "विकसित भारत 2047" के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाएँ लागू की हैं, जो समावेशी और स्थिर विकास की ओर इशारा करती हैं। इनमें कुछ प्रमुख योजनाएँ हैं:

1. आर्थिक एवं उद्योग विकास योजनाएँ –

◆ **मेक इन इंडिया (Make in India)**

- शुरूआत : 2014
- उद्देश्य : भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना।
- फोकस : ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि 25 सेक्टर।

◆ **स्टार्टअप इंडिया (Startup India)**

- शुरूआत : 2016
- उद्देश्य : नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना।
- लाभ : टैक्स छूट, फंडिंग सहायता, पंजीकरण प्रक्रिया में सरलता।

◆ **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)**

- उद्देश्य : छोटे व्यवसायों और स्वरोजगार को बिना गारंटी के ऋण देना।
- तीन श्रेणियाँ:
  - शिशु (रु. 50,000 तक)
  - किशोर (रु. 50,000–रु.5 लाख)
  - तरुण (रु. 5 लाख–रु.10 लाख)

◆ 2. डिजिटल और तकनीकी सशक्तिकरण

◆ **डिजिटल इंडिया अभियान**

- उद्देश्य : हर नागरिक को डिजिटल सेवाओं से जोड़ना।
- मुख्य पहलें:
  - डिजिलॉकर
  - ई–गवर्नेंस
  - भारतनेट परियोजना (ग्रामीण ब्रॉडबैंड)

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM)

- हर व्यक्ति को हेल्थ आईडी कार्ड देना।
- स्वास्थ्य डेटा डिजिटल रूप में संग्रहित और साझा करने योग्य बनाना।

3. सामाजिक कल्याण योजनाएँ

प्रधानमंत्री जन–धन योजना (PMJDY)

- उद्देश्य : हर नागरिक को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना।
- लाभ : जीरो बैलेंस खाता, बीमा, पेंशन।

उज्ज्वला योजना

- उद्देश्य : गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना।
- खासकर ग्रामीण महिलाओं को धुएँ से मुक्त रसोई देना।

स्वच्छ भारत मिशन

- उद्देश्य: खुले में शौच से मुक्ति, स्वच्छता को बढ़ावा।
- दो चरण:
  - शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय निर्माण।
  - कचरा प्रबंधन और व्यवहार परिवर्तन।

4. शिक्षा और कौशल विकास योजनाएँ

नई शिक्षा नीति 2020

- फोकस : समग्र, लचीली और कौशल–आधारित शिक्षा।
- बदलाव : 5+3+3+4 स्कूली संरचना, मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा।

कौशल भारत मिशन (Skill India)

- उद्देश्य : युवाओं को व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण देना।
- योजना : च्डझटल (प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना)

5. स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाएँ

आयुष्मान भारत योजना (PM-JAY)

- दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना।
- लाभ : प्रति परिवार रु. 5 लाख तक का मुफ्त इलाज।
- लाभार्थी : 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवार।

मिशन इंद्रधनुष

- बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण सुनिश्चित करना।

6. ग्रामीण और कृषि विकास योजनाएँ

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)

- लाभ : छोटे और सीमांत किसानों को रु. 6,000 वार्षिक सहायता।
- भुगतान : तीन किस्तों में बैंक खाते में

सीधे भेजा जाता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

- उद्देश्य : प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान का बीमा सुरक्षा देना।

मनरेगा (MGNREGA)

- ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार को साल में 100 दिन का रोजगार।

7. आवास और बुनियादी ढाँचा विकास

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

- उद्देश्य : सभी को 2022 तक 'अपना घर' देना।
- दो भाग :
  - शहरी (PMAY-Urban)
  - ग्रामीण (PMAY-Gramin)

भारतमाला परियोजना

- उद्देश्य : हाईवे नेटवर्क का निर्माण और विस्तार।
- विशेष फोकस : सीमावर्ती और दुर्गम क्षेत्र।

केंद्र सरकार की ये योजनाएँ भारत को सामाजिक, आर्थिक, और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने का प्रयास हैं। इनका उद्देश्य "विकसित भारत" की ओर मजबूत आधार तैयार करना है, जिसमें हर नागरिक को अवसर, सुविधा और गरिमा मिल सके।

केंद्र सरकार की योजनाओं की सारणी : –

क्रम	योजना का नाम	प्रारंभ वर्ष	उद्देश्य / लाभ	लक्षित समूह / क्षेत्र
1.	मेक इन इंडिया	2014	भारत को निर्माण केंद्र बनाना	विनिर्माण क्षेत्र, उद्योगपति
2.	स्टार्टअप इंडिया	2016	नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा	युवा उद्यमी
3.	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)	2015	लघु ऋण बिना गारंटी	छोटे व्यवसाय, स्वरोजगार
4.	डिजिटल इंडिया	2015	डिजिटल सेवाओं का प्रसार	नागरिक, ग्राम पंचायतें
5.	आयुष्मान भारत (PM-JAY)	2018	रु. 5 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा	गरीब परिवार
6.	प्रधानमंत्री जन–धन योजना	2014	बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच	आर्थिक रूप से कमजोर लोग
7.	उज्ज्वला योजना	2016	मुफ्त गैस कनेक्शन	बीपीएल महिलाएँ
8.	स्वच्छ भारत मिशन	2014	खुले में शौच मुक्त भारत	ग्रामीण व शहरी क्षेत्र

9.	कौशल भारत मिशन (Skill India)	2015	युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण	बेरोजगार युवा
10.	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि	2019	रु. 6000 वार्षिक सहायता	छोटे और सीमांत किसान
11.	पीएम आवास योजना (PMAY)	2015	सबको घर (2022 तक)	ग्रामीण व शहरी गरीब
12.	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)	2016	फसल नुकसान की बीमा सुरक्षा	किसान
13.	मिशन इंद्रधनुष	2014	बच्चों का पूर्ण टीकाकरण	0–2 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएँ
14.	मनरेगा	2005	100 दिन का ग्रामीण रोजगार	ग्रामीण गरीब परिवार
15.	भारतमाला परियोजना	2017	राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार	परिवहन व कनेक्टिविटी सेक्टर

इन नीतियों के संदर्भ में विकासमूलक पत्रकारिता की भूमिका

1. **सूचना का संचार :** ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों तक इन योजनाओं की सही जानकारी पहुँचाना, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें।
2. **जमीनी हकीकत की रिपोर्टिंग** : कई बार सरकारी योजनाएँ कागज पर बेहतर दिखती हैं, पर जमीन पर उनका कार्यान्वयन कमजोर होता है। विकासमूलक पत्रकारिता इन खामियों को उजागर करती है।
3. **जनहित और जागरूकता :** पत्रकारिता के जरिये लोगों को उनके अधिकारों और सरकारी लाभों की जानकारी दी जाती है, जिससे वे सशक्त बनते हैं।
4. **नीति सुधार में सहायक :** जब पत्रकार रिपोर्ट के जरिये योजनाओं की कमियाँ सामने लाते हैं, तो इससे नीति–निर्माताओं को उन्हें सुधारने का अवसर मिलता है।

विकासमूलक पत्रकारिता के मुख्य कार्य

1. **सकारात्मक दृष्टिकोण** – समस्याओं के समाधान पर केंद्रित रिपोर्टिंग।
2. **जनहित पर जोर –** आमलोगों के जीवन से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देना।
3. **जन–जागरूकता** – लोगों को उनके अधिकारों और अवसरों के बारे में जानकारी देना।
4. **नीतियों की समीक्षा** – सरकारी योजनाओं और नीतियों का विश्लेषण करना कि वे जमीनी स्तर पर कितना असर डाल रही है।

मुख्यधारा मीडिया जहाँ अक्सर शहर–केंद्रित खबरों तक सीमित रहता है, वहीं विकासमूलक पत्रकारिता ग्रामीण, आदिवासी, और पिछड़े समुदायों की आवाज बनती है।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दे : इसमें शिक्षा

की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाएँ, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार योजनाएँ आदि जैसे विकास से जुड़े मुद्दों को कवर किया जाता है।

नीतियों और योजनाओं की समीक्षा : सरकार की योजनाओं का जमीनी स्तर पर कितना असर हो रहा है, यह बताना विकासमूलक पत्रकारिता का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है।

सकारात्मक उदाहरणों को बढ़ावा देना : जो लोग समाज में बदलाव ला रहे हैं– जैसे कोई शिक्षक, स्वयंसेवी संगठन या कोई ग्राम पंचायत – उनके कार्यों को सामने लाया जाता है।

उदाहरण :

एक रिपोर्ट जिसमें बताया गया हो कि कैसे एक गाँव में महिला समूहों ने जल संरक्षण की पहल से खेती को पुनर्जीवित किया, वह विकासमूलक पत्रकारिता का उदाहरण होगा।

भारत में विकासमूलक पत्रकारिता के कुछ उल्लेखनीय उदाहरणों और प्लेटफॉर्म्स

1. उदाहरण:

(a) ''गांव कनेक्शन'' (Gaon Connection) :

भारत का पहला ग्रामीण मीडिया प्लेटफॉर्म है।

यह किसानों, ग्रामीण महिलाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे विषयों पर रिपोर्ट करता है।

उदाहरण : बुंदेलखंड में जल संकट पर विस्तृत रिपोर्टिंग और स्थानीय जल संरक्षण प्रयासों को सामने लाना।

(b) "PARI" – People's Archive of Rural India:

प्रसिद्ध पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी और पलागुम्मी साईनाथ द्वारा शुरू किया गया यह प्लेटफॉर्म ग्रामीण भारत के जीवन, समस्याओं और बदलावों को दस्तावेज करता है।

उदाहरण : महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में किसानों की आत्महत्याओं पर मानवीय रिपोर्टिंग।

C - Dainik Bhaskar और BBC Hindi (विकास विशेषांक) :

कुछ बड़े मीडिया समूहों ने भी समय–समय पर विकास आधारित विशेष रिपोर्टिंग की है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान के असर पर जमीनी रिपोर्ट।

विकासमूलक पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले प्रमुख नाम

1. **पलागुम्मी साईनाथ** – 'Everybody Loves a Good Drought' पुस्तक के लेखक और ग्रामीण पत्रकारिता के सबसे प्रसिद्ध चेहरों में से एक।
2. **रवीश कुमार** – NDTV इंडिया में रहते हुए उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे विषयों पर लगातार रिपोर्टिंग की।
3. **नरेश फर्नांडिस** (**Scroll-in**) – गहराई वाली रिपोर्टिंग और समाज केंद्रित पत्रकारिता के लिए प्रसिद्ध।

जब हम विकासमूलक पत्रकारिता की बात करते हैं ,तो सांस्कृतिक विकास भी इसी का एक पहलू है। ''एक भारत श्रेष्ठ भारत'' केंद्र सरकार की एक दूरगामी नीति है, जिसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विविधता में एकता को सुदृढ़ करना, राष्ट्र की अखंडता को मजबूत करना और विभिन्न राज्यों, भाषाओं व संस्कृतियों के बीच आपसी सहयोग व समझ को बढ़ावा देना है। जब हम इस नीति को विकासमूलक पत्रकारिता के संदर्भ में देखते हैं,तो दोनों में एक गहरा और रचनात्मक संबंध दिखाई देता है।

हम जानते हैं– भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा देश है, जहां भाषा, संस्कृति, परंपराएं और रीति–रिवाज अनेक रूपों में विद्यमान हैं। इन विविधताओं में एकता को बनाए रखना

तथा राष्ट्र को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से सुदृढ़ बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य भी है। इसी दिशा में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पहल ''एक भारत श्रेष्ठ भारत'' न केवल राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करती है, बल्कि विकास के साझा दृष्टिकोण को भी सामने लाती है। इस अभियान को सफल बनाने में विकासमूलक पत्रकारिता की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

विकसित भारत की दिशा में योगदान

विकासमूलक पत्रकारिता सरकार की जवाबदेही तय करने के साथ–साथ समाज के उन हिस्सों को भी सामने लाती है जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं। जब पत्रकारिता ग्रामीण नवाचार, महिला सशक्तिकरण, स्थानीय स्वराज, शिक्षकों की उपलब्धि या पर्यावरणीय चेतना जैसे विषयों को उजागर करती है, तब यह समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त करती है।

निष्कर्ष

विकासमूलक पत्रकारिता और केंद्र सरकार की नीतियाँ एक–दूसरे के पूरक हैं। जहाँ सरकार योजनाओं के जरिये "विकसित भारत" का सपना साकार करना चाहती है, वहीं पत्रकारिता उस प्रक्रिया को पारदर्शी, समावेशी और जनोन्मुखी बनाने में अहम भूमिका निभाती है। यदि पत्रकारिता अपने सामाजिक दायित्व को निभाए और सरकार भी आलोचनाओं को खुले मन से स्वीकार करे, तो भारत निश्चित रूप से एक समावेशी, सशक्त और विकसित राष्ट्र के रूप में उभर सकता है।

संदर्भ

- विकास संचार एवं पत्रकारिता : नादिर जाफरी, प्रकाशक –स्टार एजुकेशनल बुक्स ।
- विकास : मुद्दे एवं परिपेक्ष्य (इग्नू)
- विकासमूलक संचार की तलाश में : जगदीश्वर चतुर्वेदी (लेख)
- पत्रकारिता एवं विकास संचार : प्रो. अनिल कुमार उपाध्याय, प्रकाशक– भारती प्रकाशन, वाराणसी।
- विकास संचार तथा पत्रकारिता : बारहवीं कक्षा (गृह विज्ञान) एन.सी.ई.आर.टी.